दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

जुलाई 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- उत्तराखंड की 3 लाख महिलाएँ बनेंगी 'लखपति दीदी' 3
- दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों के वीआरएस के लिये गठित होगी कमेटी 4
- मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना 4
- जलवायु परिवर्तन का असर- उत्तराखंड में समय से पहले खिलने लगे फूल, रंग और गंध में भी अंतर 4
- स्टार्टअप रैंकिंग-2021 में उत्तराखंड ने हासिल की लीडर्स श्रेणी 5
- टूरिज्म प्रोजेक्टों में तेज़ी लाने को बनेगी राज्यस्तरीय कमेटी 6
- प्रदेशभर में मनेगा हरेला उत्सव 6
- उत्तराखंड में गठित होगा खेल विकास कोष 7
- 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में उत्तराखंड 24वें स्थान पर 7
- मुख्यमंत्री ने किया 'स्टार्ट-अप ग्रांड चैलेंज' के प्रतिभागियों को सम्मानित' 8
- राज्य सरकार ने पाँच गुना बढ़ाई गो संरक्षण भरण-पोषण की राशि 8
- बदरीनाथ में मिली काई की दुर्लभ प्रजाति: बायोडीज़ल का बन सकती है विकल्प 8
- चंपावत का प्रसिद्ध देवीधुरा 'माँ वाराही बग्वाल मेला' राजकीय मेला घोषित' 9
- उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति-2020 लागू 10
- केदारनाथ धाम में लगा ऑटोमैटिक वेदर सिस्टम 10
- अक्षय पात्र एकीकृत रसोई का उद्घाटन 11
- अनाथालयों में रह रहे बच्चों के भी बनेंगे आयुष्मान कार्ड, मिलेगा मुफ्त इलाज़ 11
- मुख्यमंत्री ने किया 'बीयोंड द मिस्टी वील, टेंपल टेल्स ऑफ उत्तराखंड' पुस्तक का विमोचन 12
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर 12
- उत्तराखंड को मिला 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेंशन)' पुरस्कार 13
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 13
- उत्तराखंड में होगा नेवले की प्रजाति 'माउंटेन वीजल'का संरक्षण 14
- उत्तराखंड में बनेगा सख्त नकलरोधी कानून 14
- स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 15
- टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड 15
- हरिद्वार में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने किया खारिज 16
- प्रदेश में खुलेंगे दो सरकारी नशामुक्ति केंद्र, 2025 तक ड्रग्स फ्री होगी देवभूमि 16

नोट :

उत्तराखंड

उत्तराखंड की 3 लाख महिलाएँ बनेंगी 'लखपति दीदी'

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के अपर सचिव (ग्राम्य विकास) आनंद स्वरूप ने बताया कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत प्रदेश की 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- आनंद स्वरूप ने बताया कि 'लखपति दीदी' योजना के तहत ऐप के माध्यम से ब्लाक और जिला स्तर पर को-ऑर्डिनेटरों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया गया है। सर्वे का काम होने के बाद एसजीएच के अलग-अलग ग्रुप को अलग-अलग काम सौंपे जाएंगे, ताकि उनकी आय प्रतिवर्ष एक लाख रुपए तक की जा सके।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं के लिये 'लखपति दीदी' योजना के तहत उन्हें कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 20 हजार नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा, ताकि अधिक-से-अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।
- वर्तमान में प्रदेश के 95 ब्लॉकों में 39,116 स्वयं सहायता समूहों में 3 लाख 5 हजार महिलाओं को संगठित कर 4 हजार 310 ग्राम संगठन और 259 क्लस्टर स्तरीय संगठनों का गठन किया गया है।
- इन संगठनों से जुड़ीं महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिये कौशल विकास के साथ टिकाऊ, सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को तमाम नए कामों में प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जाएगा।
- अभी तक एसएचजी से जुड़ीं महिलाएँ आमतौर पर आचार, पापड़, हैंडीक्राफ्ट, सब्जी, रेशम, फल जैसे कामों तक ही सीमित हैं। आने वाले दिनों में इन महिलाओं को इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, टेंट हाउस, राजमिस्त्री, खाद बनाने, आर्गेनिक खेती, एलईडी बल्ब बनाने जैसे कामों में दक्ष बनाया जाएगा।
- एसएचजी की ओर से तैयार उत्पादों के विपणन के लिये एनआरएलएम कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें एक छत के नीचे लाया जाएगा, ताकि अलग-अलग समूहों को काम बाँटकर इनकी एक चेन बनाई जा सके। इसके तहत समूहों को बैंक लोन लेने में भी आसानी होगी।
- राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार मिले, इसके लिये भी योजना के तहत प्रयास किये जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं महिलाओं के उत्पादों को उचित बाजार दिलवाने के लिये अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंतरा, पे-टीएम मॉल जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) से भी अनुबंध किया जा रहा है।
- आजीविका मिशन के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पांडेय ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में राज्य स्तरीय दो उत्तरा आउटलेट स्थापित किये जा चुके हैं। इनमें एक रानीपोखरी और एक रायपुर में स्थापित है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।
- इसके अलावा 13 जिला स्तरीय आउटलेट (सरस सेंटर), ब्लाक स्तर पर 9 क्लस्टर आउटलेट, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट और 24 ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की गई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी एक आउटलेट बनाया गया है। इसके अलावा चारधाम यात्रा रूटों पर 17 अस्थाई आउटलेट बनाए गए हैं। जहाँ एसएचजी की ओर से तैयार उत्पादों को बेचा जाता है।

नोट :

दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों के वीआरएस के लिये गठित होगी कमेटी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजावाला में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के दौरान दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों को वीआरएस देने के लिये अधिकारियों को एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग का प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र के एक स्कूल को गोद लेगा।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक आचरण नियमावली का पालन करें। पहले विभाग के सामने उचित फोरम में अपनी बात रखें। यदि इसके बाद भी समस्या का निपटारा नहीं होता, तो शिक्षक शासन स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट किसी समस्या का अंतिम विकल्प हो सकता है।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये सबसे पहले अनुशासित होना जरूरी है। विभाग में अनुशासन बनाने के लिये विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा एवं आचरण नियमावली का पालन करना होगा। कई कार्मिक अपनी बात को उचित फोरम में रखे बिना सीधे कोर्ट पहुँच जाते हैं, जिससे विभागीय कार्यों में दिक्कत पैदा होती है।
- मंत्री ने कहा कि स्कूलों में कम-से-कम 220 दिन अनिवार्य कक्षाएँ चलनी चाहिये। राज्य में अब भी सात प्रतिशत लोग निरक्षर हैं।
- गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में पहली बार चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना (MGKY) को लागू करने और राज्य में सभी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (MPACS) के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये सहकारिता सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने एकीकृत सहकारी विकास परियोजना कार्यालय में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में सचिव ने कहा कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में एमजीकेवाई का विस्तार किया जाए।
- योजनांतर्गत कृषकों एवं पशुपालकों को सहकारिता समितियों के माध्यम से पौष्टिक हरा चारा साइलेज प्रदान किया जाता है।
- सचिव ने यह भी बताया कि प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर 103 एमपीएसीएस ऑनलाइन हो चुके हैं।
- इसके अतिरिक्त सचिव ने बकरी घाटी गाँवों की समीक्षा के पश्चात् कहा कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों में भी बकरी गाँव स्थापित किये जाएंगे, जिनका आकार एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होगा।

जलवायु परिवर्तन का असर- उत्तराखंड में समय से पहले खिलने लगे फूल, रंग और गंध में भी अंतर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं क्षेत्रीय प्रभारी डॉ. एस.के. सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण न सिर्फ फूल निर्धारित समय से पहले खिलने लगे हैं, बल्कि उनके रंगों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी दुनिया में साढ़े 4 लाख ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें फूल खिलते हैं। इनमें से 40,000 प्रजातियों की वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। 20 हज़ार प्रजातियाँ ऐसी हैं, जिनमें तय समय पर फूल खिलते हैं। निश्चित तापमान और वातावरण में ही फूलों के खिलने की प्रक्रिया शुरू होती है।
- कुछ फूल ऐसे हैं, जो ऋतुओं के आने का संकेत देते हैं, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन से फूलों के खिलने के समय में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।
- डॉ. एस.के. सिंह के मुताबिक राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी अब निर्धारित समय से पहले खिलने लगा है। वहीं फूलों की घाटी में भी समय से पहले फूल खिलने की बातें सामने आ रही हैं।
- जलवायु परिवर्तन और तापमान में बढ़ोतरी से अब फूलों के रंगों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकन साइंस जर्नल करेंट बायोलॉजी में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, फूलों के पिगमेंट में भी रासायनिक बदलाव देखने को मिल रहा है। पिगमेंट ही पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणों का सबसे अधिक असर उच्च हिमालयी क्षेत्रों के फूलों पर देखने को मिल रहा है।
- शोध में यह बात भी सामने आई कि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन से ओज़ोन परत के क्षरण और अधिक अल्ट्रावायलेट किरणों के धरती पर आने से फूलों के परागकणों पर भी असर पड़ा है। यह भी फूलों के खिलने के समय और रंगों में बदलाव का एक कारण रहा है।

स्टार्टअप रैंकिंग-2021 में उत्तराखंड ने हासिल की लीडर्स श्रेणी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग-2021 में उत्तराखंड ने लीडर्स श्रेणी हासिल की है, जबकि गुजरात और कर्नाटक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की रैंकिंग मिली है।

प्रमुख बिंदु

- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये सरकार की ओर से किये जा रहे सुधार के चलते उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में एक पायदान आगे बढ़ा है। नवाचार आइडिया को स्टार्टअप के रूप में स्थापित करने के लिये सरकार की ओर से सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, जिससे केंद्र की स्टार्टअप रैंकिंग में राज्य को कामयाबी मिल रही है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2018 की रैंकिंग में उत्तराखंड को इमर्जिंग (उभरते) और 2019 में एस्पायरिंग (आकांक्षी) श्रेणी में जगह मिली थी।
- उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि सरकार की नीतियों से स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को सरकार वित्तीय प्रोत्साहन के साथ तकनीकी सहयोग भी प्रदान कर रही है।
- सरकार की ओर से स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में नवाचार आइडिया पर 128 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। प्रदेश की स्टार्टअप नीति, 2018 के तहत सरकार की ओर से स्टार्टअप को कारोबार स्थापित करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जिसमें एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत छूट, उत्पाद का पेटेंट कराने के लिये 1 से 5 लाख रुपए की सहायता, स्टार्टअप को 10 से 15 हजार रुपए तक मासिक भत्ता भी दिया जा रहा है।
- नवाचार आइडिया को कारोबार में स्थापित करने के लिये सरकार ने 13 इन्क्यूबेशन सेंटरों को मान्यता दी है। जहाँ पर स्टार्टअप को प्रोजेक्ट तैयार करने के लिये मशीनरी, तकनीकी सहयोग की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में इन्क्यूबेशन सेंटर खुलने से राज्य को स्टार्टअप को प्रोजेक्ट बनाने के लिये दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ता है।
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने वर्ष 2018 में स्टार्टअप नीति लागू की है। अब सरकार स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन सेंटर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये सुविधाएँ बढ़ाने को नीति में संशोधन की तैयारी कर रही है।

नोट :

टूरिज्म प्रोजेक्टों में तेज़ी लाने को बनेगी राज्यस्तरीय कमेटी

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आतिथ्य क्षेत्र में निवेश की संभावना कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि पर्यटन प्रोजेक्टों में तेज़ी लाने के लिये राज्यस्तरीय कमेटी बनेगी।

प्रमुख बिंदु

- राजपुर रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र के विकास और निवेशकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) की ओर से प्रदेश में आतिथ्य क्षेत्र में निवेश की संभावना विषय पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की।
- इस राज्यस्तरीय कमेटी का गठन सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस कमेटी में वित्त, आवास, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य सबंधित विभागों के अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, जिनके तहत एयर फ्यूल के दामों में 18 प्रतिशत की कमी की गई है। तीन महीने बाद दोबारा सभी पर्यटन निवेशकों से संवाद होगा।
- सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि निवेशकों के लिये सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों का सरलीकरण किया जाएगा।
- पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद पर्यटन में निवेश की असीम संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में 5 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश पर्यटन के क्षेत्र में करना है।

प्रदेशभर में मनेगा हरेला उत्सव

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन मुख्यालय परिसर में मंथन सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 16 जुलाई को हरेला पर्व प्रदेशभर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- वन मंत्री ने कहा कि इस बार क्षेत्र की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से पौधों का चयन किया जाएगा। इसके लिये पौध और तकनीक वन विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी।
- इस दौरान वन विभाग ने प्रदेशभर में 15 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत पहली बार इस उत्सव पर 50 प्रतिशत से अधिक फलदार पौधे रोपे जाएंगे।
- हरेला पर्व पर स्कूल, कॉलेज और वन पंचायतों की सहभागिता को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा। पौधे लगाने के बाद वह जिंदा भी रहें और आने वाले समय में समाज को इनका लाभ मिले, इसके लिये प्रयास किये जाएंगे।
- वन पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से इस बार फलदार पौधरोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में वहाँ के लोगों की आजीविका इनसे जुड़ सके।
- वन मंत्री ने कहा कि पुलिस वन और मेरा वन जैसी तमाम दूसरी वाटिकाएँ प्रदेशभर में विकसित की जाएंगी। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और तमाम विभागों को यह जिम्मा सौंपा जाएगा। लोग इन वाटिकाओं में अपने, परिजनों और दिवंगतों के नाम से पौधे लगा सकेंगे। इन पौधों को जिंदा रखने और संवारने की ज़िम्मेदारी भी संबंधित व्यक्ति को ही दी जाएगी।

नोट :

उत्तराखंड में गठित होगा खेल विकास कोष

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में एक 'खेल विकास कोष' का गठन करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने अधिकारियों को केरल, हरियाणा और ओडिशा की नीतियों का अध्ययन करने को कहा, ताकि खेल विभाग आर्थिक रूप से मजबूत हो और खिलाड़ियों के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें।
- योजना के तहत कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) और अन्य संसाधनों से फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 29 अगस्त (खेल दिवस) को औपचारिक रूप से 'खेल छात्रवृत्ति योजना' का शुभारंभ करेंगे।
- 'मुख्यमंत्री उभरते खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना' के तहत प्रत्येक जिले के 150 युवाओं (8-14 वर्ष आयु वर्ग) को 1500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह खेल कौशल विकसित करने में मदद के साथ ही भविष्य के खिलाड़ियों के पोषण के लिये सहायता प्रदान करेगी।

'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में उत्तराखंड 24वें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को जारी 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' के पहले संस्करण में उत्तराखंड पूरे देश में 24वें पायदान पर है। इस सूचकांक में ओडिशा पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हैं।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण जारी किया।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में ओडिशा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा 788 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 0.758 स्कोर के साथ दूसरे और सिक्किम 0.710 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा तीन केंद्रशासित प्रदेशों में, जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव 802 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- एनएफएसए लागू करने के मामले में उत्तराखंड का प्रदर्शन न केवल राष्ट्रीय स्तर, बल्कि पूर्वोत्तर व हिमालयी 14 राज्यों में भी काफी पीछे रहा है। इस सूची में त्रिपुरा पहले, हिमाचल प्रदेश दूसरे और सिक्किम तीसरे नंबर पर है, जबकि उत्तराखंड 0.637 स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर है।
- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति एवं प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर प्रकाश डालता है और सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है, जो टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं- i) एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और iii) पोषण संबंधी पहल।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया 'स्टार्ट-अप ग्रांड चैलेंज' के प्रतिभागियों को सम्मानित'

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 'स्टार्ट-अप ग्रांड चैलेंज' कार्यक्रम में 10 प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा तैयार की गई वेलनेस रिपोर्ट का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के 10 युवा प्रतिभागियों को सर्वश्रेष्ठ नवाचार आइडिया का ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार स्वरूप 50-50 हज़ार रुपए की राशि दी गई।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने स्टार्ट-अप उत्तराखंड के तहत 'आइडिया ग्रेट चैलेंज' के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तथा स्टार्ट-अप को एक साल तक दिया जाने वाला मासिक भत्ता 10 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए करने की घोषणा की।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी द्वारा एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं को दिया जाने वाला मासिक भत्ता 15 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपए किये जाने की घोषणा की गई।

राज्य सरकार ने पाँच गुना बढ़ाई गो संरक्षण भरण-पोषण की राशि

चर्चा में क्यों ?

9 जुलाई, 2022 को विधानसभा स्थित कार्यालय में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में गो सदन राजकीय अनुदान चयन समिति की बैठक के दौरान संरक्षित पशुओं के भरण-पोषण की राशि पाँच गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में राज्य में संचालित मान्यताप्राप्त गो सदनों को प्रति पशु मिलने वाली राशि को छः रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए किया गया है।
- वर्तमान में प्रदेश में 39 मान्यता प्राप्त गो सदन संचालित हैं। इनमें लगभग 10 हज़ार पशुओं का भरण-पोषण किया जा रहा है। पशुचारे के लिये भूसे की कीमत बढ़ने से उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर संरक्षित पशुओं के भरण-पोषण राशि में पाँच गुना की बढ़ोतरी की गई।
- इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के माध्यम से गो सदनों को गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों व सोलर लाइट के लिये अनुदान राशि दी जाएगी। गो सदनों को भूसा स्टोर, गोशाला निर्माण के लिये 60 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाएगी।
- पशुपालन मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में गो सदनों को राजकीय अनुदान देने के लिये 15 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। संरक्षित पशुओं के कल्याण गतिविधियों के संचालन हेतु उत्तराखंड गोवंश संरक्षण निधि को 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
- पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लावारिस पशुओं के संरक्षण के लिये सरकार जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 'ग्राम गो सेवक योजना' शुरू करेगी। इसमें गाँव स्तर पर ग्राम गो सेवकों के माध्यम से संरक्षित पशुओं का भरण-पोषण किया जाएगा।
- 200 से अधिक संरक्षित पशुओं का भरण-पोषण करने वाले गो सदनों को दक्षता सुधार गतिविधियों, उपकरण, औज़ार, सामग्री के लिये 90 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

बदरीनाथ में मिली काई की दुर्लभ प्रजाति: बायोडीज़ल का बन सकती है विकल्प

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एचएनबी गढ़वाल (केंद्रीय) विश्वविद्यालय के वनस्पति एवं सूक्ष्म जैविकी (बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी) विभाग ने बदरीनाथ के नारद कुंड में दुर्लभ प्रजाति के सूक्ष्म शैवाल (काई) की खोज की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह शैवाल अभी तक भारत के गुजरात राज्य सहित दो देशों में ही पाया गया है। यह प्रजाति इससे पूर्व वर्ष 1980 में गुजरात में देखी गई थी। साथ ही, वर्ष 1966 में अमेरिका और वर्ष 1987 में बांग्लादेश में भी इसे देखा गया था।
- सूडोबोहलिनिया नामक यह सूक्ष्म शैवाल बायोडीज़ल (जैव ईंधन) का सर्वोत्तम विकल्प बन सकता है।
- गढ़वाल विवि के बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सहायक प्रो. डॉ. धनंजय कुमार के निर्देशन में शोध कर रहीं प्रीति सिंह ने इस दुर्लभ प्रजाति के सूक्ष्म शैवाल को खोजने के साथ ही इसकी उत्पादकता का विश्लेषण किया है।
- प्रीति सिंह ने बदरीनाथ में तप्तकुंड के नीचे स्थित नारद कुंड की दीवार से शैवाल के नमूने लिये थे। इस कुंड में तप्त कुंड का गर्म पानी गिरता है। पानी का तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है।
- दीवार से नमूने लेने के बाद उन्होंने विभाग की प्रयोगशाला में इसका उत्पादन किया। एक साल तक चले अध्ययन में उन्हें सामान्य शैवाल के साथ ही चार सूक्ष्म शैवाल की प्रजातियाँ मिलीं। इनमें तीन तो अन्य जगहों पर देखी गईं थीं, लेकिन एक प्रजाति बिल्कुल अलग मिली।
- प्रीति सिंह ने बताया कि इस शैवाल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। लगभग 5 माइक्रोमीटर के इस शैवाल की बाहरी सतह पर काँटों के समान आकृति देखी गई। यह शैवाल तेज़ी से फैलता है और इसमें लिपिड (वसा) की भी अच्छी-खासी मात्रा होती है।
- दुर्लभ प्रजाति के सूक्ष्म शैवाल मिलने के बाद बायोडीज़ल बनाने में इसकी उपयोगिता पर शोध किया गया। भारत में कुछ स्थानों पर शैवाल से बायोडीज़ल बनाने का काम चल रहा है। विश्वविद्यालय की एल्गल लैब में शोधकर्त्ताओं ने लगभग 109 प्रजाति के शैवालों में लिपिड का तुलनात्मक अध्ययन किया। सामान्यतया शैवाल में 25 से 30 फीसदी लिपिड मिलता है। वहीं, सूडोबोहलिनिया में सामान्य परिस्थिति में सबसे अधिक 33 फीसदी लिपिड मिला। अनुकूल वातावरण मिलने पर लिपिड की मात्रा काफी बढ़ गई, जो बायोडीज़ल बनाने के लिये काफी बेहतर है। लिपिड ही बायोडीज़ल का प्रमुख स्रोत है।
- गौरतलब है कि पेट्रोलियम ईंधन की सीमित मात्रा को देखते हुए विकल्प के तौर पर बायोडीज़ल पर ज़ोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की बायोफ्यूल नीति के तहत पेट्रोलियम ईंधन में 20 प्रतिशत तक बायोडीज़ल मिलाने का लक्ष्य है, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि सरकार सूक्ष्म शैवाल के उत्पादन पर ज़ोर देती है, तो सूडोबोहलिनिया जैसी प्रजातियाँ बेहतर विकल्प बन सकती हैं।

चंपावत का प्रसिद्ध देवीधुरा 'माँ वाराही बग्वाल मेला' राजकीय मेला घोषित'

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के प्रसिद्ध देवीधुरा 'माँ वाराही बग्वाल मेले' को राजकीय मेला घोषित किया। उन्होंने मुख्य सचिव को तत्काल इसका जीओ जारी करने के आदेश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि कुछ समय पहले चंपावत में मुख्यमंत्री ने मेले को राजकीय मेला का दर्जा देने की घोषणा की थी। राज्य मेला घोषित करने के बाद से इस साल पहली बार राज्य सरकार के तत्त्वावधान में मेला आयोजित होगा। वर्तमान में ज़िला पंचायत के स्तर पर मेले का आयोजन होता है।
- चंपावत ज़िले के प्रसिद्ध देवीधुरा में 'माँ वाराही मंदिर' में रक्षाबंधन के दिन होने वाले प्रसिद्ध बग्वाल मेले को 'पत्थर मार' मेला भी कहा जाता है। इस मेले को देखने देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु देवीधुरा पहुँचते हैं।
- ऐसा माना जाता है कि देवीधुरा में बग्वाल का यह खेल पौराणिक काल से चला आ रहा है। कुछ लोग इसे कत्यूर शासन से चला आ रहा पारंपरिक त्योहार मानते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे काली कुमाऊँ से जोड़कर देखते हैं।
- प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पौराणिक काल में चार खामों के लोगों द्वारा अपनी आराध्या वाराही देवी को मनाने के लिये नर बलि देने की प्रथा थी। माँ वाराही को प्रसन्न करने के लिये चारों खामों के लोगों में से हर साल एक नर बलि दी जाती थी। बताया जाता है कि एक साल चमियाल खाम की एक वृद्धा परिवार की नर बलि की बारी थी। परिवार में वृद्धा और उसका पौत्र ही जीवित थे। महिला ने अपने पौत्र की रक्षा के लिये माँ वाराही की स्तुति की। माँ वाराही ने वृद्धा को दर्शन दिये और मंदिर परिसर में चार खामों के बीच बग्वाल खेलने के निर्देश दिये, तब से बग्वाल की प्रथा शुरू हुई।

नोट :

- चंपावत जनपद के पाटी ब्लॉक के देवीधुरा में माँ वाराही धाम मंदिर के खोलीखांड दुबाचौड़ में हर साल अषाढ़ी कौथिक (रक्षाबंधन) के दिन बग्वाल मेला होता है। पत्थर से शुरू यह बग्वाल मेला बीते कुछ वर्षों से फल-फूलों से खेली जाती रही है। लाखों लोगों की मौज़ूदगी में होने वाली बग्वाल मेले में चार खामों (चम्याल, गहरवाल, लमगड़िया और वालिग) के अलावा सात थोकों के योद्धा फर्रों के साथ हिस्सा लेते हैं।
- बग्वाल वाराही मंदिर के प्रांगण खोलीखांड में खेली जाती है। इसे चारों खामों के युवक और बुजुर्ग मिलकर खेलते हैं। लमगड़िया व वालिग खामों के रणबाँकुरे एक तरफ, जबकि दूसरी ओर गहड़वाल और चम्याल खाम के रणबाँकुरे डटे रहते हैं।

उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति-2020 लागू

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा निदेशालय में 'बाल वाटिका' (प्राइमरी से पहले की कक्षा) का शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति-2020 लागू की। सरकार का दावा है कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के सभी विकासखंडों के आँगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में 'बाल वाटिका' कक्षाएँ आरंभ कर दी गईं। निजी स्कूलों में नर्सरी में होने वाली पढ़ाई, अब आँगनबाड़ी एवं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 'बाल वाटिका' कक्षा में कराई जाएगी।
- राज्य में 20 हज़ार से अधिक आँगनबाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। प्रथम चरण में इनमें से शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पाँच हज़ार आँगनबाड़ी केंद्रों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू होगा।
- आँगनबाड़ी केंद्रों में 'बाल वाटिका' कक्षाओं में बच्चों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाया जाएगा। इसके लिये पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने पाठ्यक्रम में आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व शिक्षकों के लिये हस्तपुस्तिका और बच्चों के लिये तीन अभ्यास पुस्तिकाएँ (स्वास्थ्य, संवाद एवं सृजन) तैयार की हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण एवं एससीईआरटी भवन का शिलान्यास भी किया। उन्होंने बच्चों में उद्यमिता के विकास के लिये पुस्तक एवं कैरियर कार्ड का विमोचन किया, साथ ही क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण आँगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत की घोषणा की।
- शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूल परिसर में 4,447 आँगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों में प्री-प्राइमरी से कक्षाओं को शुरू कर छात्र-छात्राओं को कक्षा एक के लिये तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से प्री-प्राइमरी को 'बाल वाटिका' नाम दिया गया है। विभाग की ओर से इसके लिये अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।
- उत्तराखंड में 20 हज़ार 67 आँगनबाड़ी केंद्र मंजूर हैं। इसमें से 20 हज़ार 17 आँगनबाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केंद्रों में 14,555 आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता तैनात हैं। इसके अलावा आँगनबाड़ी केंद्रों में 14,249 सहायिकाएँ एवं 4,941 मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता कार्य कर रही हैं।

केदारनाथ धाम में लगा ऑटोमैटिक वेदर सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2022 को रुद्रप्रयाग के ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि केदारनाथ में मेरु-सुमेरु पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर ऑटोमैटिक वेदर सिस्टम (एडब्ल्यूएस) स्थापित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस ऑटोमैटिक वेदर सिस्टम से वहाँ के मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी, साथ ही बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान मिलने से ज़रूरी व्यवस्थाएँ करने में भी मदद मिलेगी।

नोट :

- इसके साथ ही बरसाती सीजन व अन्य मौकों पर केदारनाथ यात्रा के संचालन को लेकर पहले से ही निर्णय लिये जा सकेंगे। इसके अलावा चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और हेलीकॉप्टर संचालन में भी मदद मिलेगी।
- गौरतलब है कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर बारह ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ ही चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिये खुलता है।

अक्षय पात्र एकीकृत रसोई का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुद्धोवाला देहरादून में अक्षय पात्र, फाउंडेशन, द हंस फाउंडेशन तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से 63वें केंद्रीकृत मिड-डे-मील किचन का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्कूलों के बच्चों को मिड-डे-मील पहुँचाने के लिये वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार, अक्षय पात्र फाउंडेशन एवं द हंस फाउंडेशन के सामूहिक प्रयासों से बच्चों को उच्च गुणवत्तायुक्त एवं पौष्टिक भोजन की शुरुआत हुई है। अभी इस मिड-डे-मील की शुरुआत 120 स्कूलों के 15 हज़ार से अधिक बच्चों के लिये की गई है।
- भविष्य में 500 से अधिक स्कूलों के 35 हज़ार से अधिक बच्चों के लिये केंद्रीकृत किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
- अक्षय पात्र फाउंडेशन, द हंस फाउंडेशन तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से जो केंद्रीकृत किचन का शुभारंभ किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन परोसा जाएगा। राज्य में 5 लाख से अधिक बच्चों को सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि हंस फाउंडेशन एवं अक्षय पात्र फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से राज्य में दूसरी एकीकृत रसोई की शुरुआत की गई है, इससे पहले गदरपुर में एकीकृत रसोई का संचालन शुरू कर दिया गया है।

अनाथालयों में रह रहे बच्चों के भी बनेंगे आयुष्मान कार्ड, मिलेगा मुफ्त इलाज़

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अनाथालयों में रहने वाले बेसहारा बच्चों को भी 'आयुष्मान योजना' में मुफ्त इलाज़ की सुविधा मिलेगी। सरकार ने ऐसे बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस संबंध में योजना को संचालित करने हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं।
- 'आयुष्मान योजना' के तहत नवजात से लेकर चार साल तक के दस हज़ार से अधिक बीमार नौनिहालों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध की गई। उन्हें रोगमुक्त रखने के उद्देश्य से ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक दस हज़ार से अधिक बीमार बच्चों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 1,397 बालक एवं 8,700 बालिकाएँ शामिल हैं। इस पर सरकार ने 38 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।
- डॉ. रावत ने बताया कि 'आयुष्मान योजना' का बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सभी लाभ उठा रहे हैं। योजना में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज़ की सुविधा है। राज्य में अब तक 32 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। लाभार्थियों के विभिन्न रोगों के उपचार पर 868 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं।
- प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने से वंचित रह गए लोगों के कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के दौरान नि:शुल्क उपचार उपलब्ध हो सके।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया 'बीयोंड द मिस्टी वील, टेंपल टेल्स ऑफ उत्तराखंड' पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आराधना जौहरी (सेवानिवृत्त आई.ए.एस.) द्वारा उत्तराखंड के मंदिरों पर अंग्रेजी में लिखी पुस्तक 'बीयोंड द मिस्टी वील, टेंपल टेल्स ऑफ उत्तराखंड' (BEYOND THE MISTY VEIL, Temple Tales of Uttarakhand) का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक की लेखिका आराधना जौहरी को बधाई देते हुए कहा कि यह पुस्तक देश-विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों के एक प्रामाणिक परिचय के रूप में जानी जाएगी। इस पुस्तक से लोगों को बेहतरीन जानकारी मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों पर आधारित यह पुस्तक देश की संस्कृति और माइथोलॉजी के बारे मे अवगत कराती है।
- इस पुस्तक से उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को अनगिनत मंदिरों और उनसे जुड़ी लोक गाथाओं के बारे में पता चलेगा।
- पुस्तक की लेखिका आराधना जौहरी नैनीताल की डीएम रही हैं। नैनीताल में पोस्टिंग के दौरान वे स्वयं मंदिरों तक गईं और वहाँ की तमाम जानकारियाँ पुस्तक में देने की कोशिश की है। 300 पृष्ठ की पुस्तक में तीन वर्ष तक शोध किया गया है।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2021 में 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
- 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर हैं। ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर हैं।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्द्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे।
- इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमशः अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

नोट :

उत्तराखंड को मिला 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेंशन)' पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें उत्तराखंड को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेंशन)' पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने बताया कि अभी तक उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अंतर्गत तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- गौरतलब है कि नेशनल फिल्म अवार्ड की इस कैटेगरी में 13 राज्यों ने सहभागिता की थी। मध्य प्रदेश को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट'का पुरस्कार मिला, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेंशन)' का पुरस्कार दिया गया।
- के.एस. चौहान के अनुसार उत्तराखंड फिल्मकारों के लिये पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। फिल्मों व धारावाहिकों की शूटिंग के लिये अनुकूल माहौल यहाँ उपलब्ध है। उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता फिल्मकारों को यहाँ शूटिंग के लिये आकर्षित करती है।
- उत्तराखंड की फिल्म नीति से आकर्षित होकर पिछले पाँच वर्षों के दौरान ही छह सौ से अधिक फिल्मों व धारावाहिकों की यहाँ शूटिंग हो चुकी है। वर्ष 2015 से लेकर अब तक उत्तराखंड में शूटिंग के लिये कुल 784 फिल्म अनुमति प्रमाण-पत्र जारी किये गए हैं।
- उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में उत्तराखंड शूटिंग के लिहाज से फिल्म हब बनने जा रहा है। इससे उत्तराखंड में रोज़गार के साधन बढ़ने के साथ-साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी भारी वृद्धि हो रही है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत उत्तराखंड को वर्ष 2022-23 के लिये 135 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा कि पंचायतों में विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिये केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से धनराशि की स्वीकृति देने का आग्रह किया गया था। इस पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य को 135 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।
- इस धनराशि से त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण, क्षमता विकास, भ्रमण के साथ ग्राम पंचायत के सतत विकास के निर्धारित 9 लक्ष्यों की पूर्ति की जाएगी। इससे त्रिस्तरीय पंचायतों को मज़बूती मिलेगी।
- मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिये मानदेय तय किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों के खर्चों के लिये गाइडलाइन जारी की जाएगी।।
- प्रदेश के 95 विकास खंडों में एक-एक कॉम्पेक्टर, ज़िला पंचायत में पार्किंग, 200 पंचायत भवन का निर्माण, 500 ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण, 100 पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा।
- प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में साफ-सफाई के लिये एक-एक वैक्यूम आधारित सफाई मशीन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम स्वराज अभियान की कार्ययोजना में पूर्व से निर्मित राज्य, ज़िला व ब्लॉक स्तरीय पंचायत रिसोर्स सेंटर के लिये संकाय उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

नोट :

उत्तराखंड में होगा नेवले की प्रजाति 'माउंटेन वीजल'का संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि वन विभाग की अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) ने उच्च हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितकीय संतुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेवले की प्रजाति 'माउंटेन वीजल'का राज्य में संरक्षण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि विभाग की अनुसंधान शाखा ने इसके लिये पाँचवर्षीय कार्ययोजना तैयार की है। जल्द ही बदरीनाथ, हरकी दून, हर्षिल समेत अन्य स्थानों पर माउंटेन वीजल (Mountain Weasel) का अध्ययन शुरू किया जाएगा।
- उच्च हिमालयी क्षेत्र में तीन हज़ार मीटर से अधिक ऊँचाई पर पाई जाने वाली नेवले की यह प्रजाति भारत में लद्दाख में पाई जाती है। लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में भी इसका संरक्षण होगा।
- सामान्य तौर पर दिखने वाले नेवलों से कुछ अलग माउंटेन वीजल पतला शरीर और गर्दन, छोटे पैर और छोटे सिर वाला एकांतप्रिय स्तनधारी प्राणी है। मस्टेलिडे परिवार (family Mustelidae) का यह जीव दिखने में खूबसूरत भी है।
- उत्तराखंड में माउंटेन वीजल की चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह उच्च हिमालयी क्षेत्र में चूहे, पीका जैसी प्रजातियों का शिकार कर इनकी संख्या को विनियमित करने में प्राकृतिक रूप से मददगार भी है।
- गौरतलब है कि माउंटेन वीजल (मुस्टेला अल्ताइका), जिसे पेल वीजल, अल्ताई वीजल या सोलोंगोई के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यरूप से उच्च ऊँचाई वाले वातावरण, साथ ही चट्टानी टुंड्रा और घास वाले वुडलैंड्स में रहता है।
- इस प्रजाति का भौगोलिक वितरण कज़ाखस्तान, तिब्बत और हिमालय से लेकर मंगोलिया, उत्तर-पूर्वी चीन और दक्षिणी साइबेरिया तक एशिया के कुछ हिस्सों में है। हालाँकि, इस प्रजाति के लिये सबसे अहम क्षेत्र लद्दाख, भारत है।

उत्तराखंड में बनेगा सख्त नकलरोधी कानून

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयोग ने नए नकलरोधी कानून का प्रस्ताव पास कर दिया है। राजस्थान और एसएससी के नकलरोधी कानून का अध्ययन करने के बाद आयोग इसका ड्राफ्ट शासन को भेजेगा।

प्रमुख बिंदु

- स्नातकस्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सख्त नकलरोधी कानून बनाया जा रहा है। यह कानून इसी साल फरवरी में आए राजस्थान के नकलरोधी कानून की तर्ज़ पर सख्त होगा।
- अभी तक पेपर लीक का कोई भी मामला प्रकाश में आने के बाद उत्तराखंड के नकलरोधी कानून के तहत आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120 बी या हाईटेक नकल होने पर आईटी एक्ट में ही मुकदमे दर्ज़ होते हैं।
- राजस्थान के नकलरोधी कानून की तर्ज़ पर नकल गिरोह के सदस्यों पर दस लाख से दस करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। इसके अलावा उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकेगी। साथ ही, नकल का अपराध साबित होने पर पांच से दस साल की सज़ा का भी प्रावधान किया जाएगा।
- अगर कोई छात्र/उम्मीदवार किसी नकल गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उस पर एक लाख रुपए जुर्माने के साथ ही तीन साल तक की सज़ा भी हो सकेगी। अगर छात्र/उम्मीदवार उस नकल गिरोह का सदस्य पाया गया तो गिरोह के हिसाब से ही उस पर कार्रवाई की जाएगी।
- आयोग की ओर से नकल रोकने के लिये यह भी नया प्रावधान किया जा रहा है कि यदि कोई छात्र/उम्मीदवार नकल करते पकड़ा जाता है तो वह दो साल तक किसी भी तरह की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेगा।
- राजस्थान की तर्ज़ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल को संज्ञेय और गैर- जमानती अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। नकल और पेपर लीक की जाँच एडिशनल एसपी स्तर का अफसर ही कर सकेगा। नकल रोकने के लिये जाँच एजेंसी में एंटी चीटिंग सेल भी बनाई जा सकती है।

नोट :

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि 'स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार' में राज्य स्तर पर 26 स्कूलों का चयन किया गया है। चुने गए स्कूलों में से आठ को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये भेजा जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य स्तर पर चयनित 26 स्कूलों में 20 स्कूल ओवरआल कैटेगरी में आए हैं, जबकि छह स्कूलों का चयन सब कैटेगरी में हुआ है। राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी 26 स्कूलों को इस महीने के भीतर ही सम्मानित किया जाएगा।
- बंशीधर तिवारी ने बताया कि राज्यस्तरीय ओवरआल कैटेगरी में गढ़वाल मंडल से 11 तथा कुमाऊं मंडल से 9 स्कूल चुने गए हैं।
- राज्यस्तरीय सब कैटेगरी में पीएस बासोट, भिकियासैंण (अल्मोड़ा), केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल), जवाहर नवोदय विद्यालय जयहरीखाल (पौड़ी), केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी रायपुर और केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप, सहसपुर (देहरादून) तथा स्काईवार्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कृष्ण नगर, रुड़की (हरिद्वार) चुने गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 से 'स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार' शुरू किया था।
- राज्य स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिये ओवरऑल कैटेगरी में 100 और सब कैटेगरी में 73 स्कूलों का चयन किया गया था। स्कूलों की रैंकिंग के आधार पर अंतिम 26 स्कूलों को चुना गया है।

टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुम्का ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार पहाड़ में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिये टनल पार्किंग की शुरुआत कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार का मानना है कि टनल पार्किंग अभी तक देश में कहीं भी नहीं है। उत्तराखंड इस तरह का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इससे निश्चित तौर पर पार्किंग की बड़ी समस्या का समाधान होगा।
- पीसी दुम्का ने बताया कि टनल निर्माण को लेकर अभी काम शुरुआती चरण में है। जब इनकी डीपीआर बनेगी तो जहाँ जिस तरह की स्वीकृति की ज़रूरत होगी, उसे पूरा किया जाएगा। अभी तक जो टनल स्थल चिह्नित हुए हैं, वे ऐसे हैं कि सड़क के एक तरफ से टनल में गाड़ी पार्क होगी और दूसरी तरफ सड़क पर बाहर निकल जाएगी।
- प्रदेश भर में कुल करीब 180 पार्किंग स्थल चिह्नित किये गए हैं, जिनमें टिहरी और पौड़ी ज़िले में पहले चरण में 12 टनल पार्किंग के स्थान चिह्नित किये गए हैं।
- एनएचआईडीसीएल के अलावा टनल पार्किंग निर्माण के लिये कैबिनेट ने टीएचडीसी, यूजेवीएनएल और आरवीएनएल को कार्यदायी संस्था बना दिया है।
- आरवीएनएल पहले से ही पहाड़ में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन का काम कर रही है। आरवीएनएल ने कई बड़ी टनल का निर्माण भी किया है। वहीं, यूजेवीएनएल और टीएचडीसी ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिये टनल निर्माण किये हैं।
- टनल पार्किंग बनाने में राज्य सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इनमें सबसे पहले चुनौती पर्यावरणीय स्वीकृति की है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति के बाद ही काम शुरू हो सकेगा। ऐसी ही अनुमति की वजह से प्रदेश में कई जल विद्युत परियोजनाएँ अटकी पड़ी हैं।
- दूसरी ओर, इन टनल के निर्माण के दौरान निकलने वाला मलबा भी बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है। हालाँकि, सरकार का तर्क है कि सभी नियमों का पालन करते हुए टनल निर्माण किये जाएंगे।

नोट :

- वही पर्यावरणविदों का मानना है कि टनल पार्किंग पहाड़ के महाविनाश की पटकथा साबित होगी। अगर प्रदेश में 558 बांध बन गए तो करीब डेढ़ हज़ार किमी. सुरंगें बनेंगी। लाखों लोग टनल पर आ जाएंगे। रेल लाइन की वजह से जहाँ भी टनल निर्माण हुए हैं, वहाँ ऊपर के गाँवों में दरारें आ गई हैं।

हरिद्वार में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने किया खारिज

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के उद्योग विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड द्वारा हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र बीएचईएल में प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने हेतु भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय से हरिद्वार बीएचईएल औद्योगिक क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की कवायद शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) ने 100 एकड़ ज़मीन का चयन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी।
- प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिये केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन पहले चरण में चार मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाने हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल को केंद्र ने मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिये उपयुक्त पाया, जबकि उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के प्रस्ताव को अनुपयुक्त मानते हुए अस्वीकार किया गया है।
- केंद्र सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत पार्क को विकसित करने के लिये केंद्र की ओर से बजट दिया जाता है।
- सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिये चयनित ज़मीन को अब अन्य उद्योगों को स्थापित करने हेतु विकसित किया जाएगा।
- प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क में सर्जिकल व मेडिकल उपकरण बनाने वाले फार्मास्युटिकल्स उद्योग स्थापित होने थे, जहाँ पर उन्हें सभी तरह की सुविधाएँ दी जानी थीं।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड फार्मा उद्योग का हब है। देहरादून, हरिद्वार में तीन सौ से अधिक फार्मास्युटिकल कंपनियाँ दवा बना रही हैं। राज्य से दवाइयों को निर्यात भी किया जा रहा है।

प्रदेश में खुलेंगे दो सरकारी नशामुक्ति केंद्र, 2025 तक ड्रग्स फ्री होगी देवभूमि

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नार्को समन्वय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिये मिशन मोड में काम करने और राज्य में दो सरकारी नशामुक्ति केंद्र खोलने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ड्रग्स लेने वाले बच्चों और युवाओं की सही तरीके से काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाए। कॉलेजों में एडमिशन के समय विशेष काउंसिल की जाए।
- उन्होंने कहा कि ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने वाले बच्चों के साथ अपराधियों की तरह बर्ताव न करके उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए। कॉलेजों में अभिभावक-शिक्षकों की बैठक नियमित रूप से की जाए।
- मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित विभागों के सहयोग से एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स को सक्रिय किया जाए।

नोट :